

प्रेषक,

नितिन कुमार गुप्त,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
संस्थागत वित्त महानिदेशालय,  
उ० प्र०, 16-विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

**वित्त (संस्थागत) अनुभाग-35**

**लखनऊ: दिनांक: ६ जनवरी, 2023**

विषय: मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23 नवम्बर, 2022 को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ० प्र०) की बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-6768/एसएलबीसी/2022-23 दिनांक 06.12.2022 का कृपया संदर्भ गृहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23 नवम्बर, 2022 को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ० प्र०) की बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था। कार्यवृत्त पर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, जिसकी प्रति संलग्न है।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीय,

Signed by नितिन कुमार  
गुप्त (नितिन कुमार गुप्त)

Date: 06 जनवरी 2023 | 11:25:09

Reason: Approved



Director General <directorgeneral.difup@gmail.com>

**FW: Draft minutes of the SLBC meeting held on 23.11.2022**

1 message

Slbc Department , Up <slbc.up@bankofbaroda.com>

Tue, Dec 6, 2022 at 12:30 PM

To: Director General <directorgeneral.difup@gmail.com>, "director.dif@gmail.com" <director.dif@gmail.com>, SHIV SINGH <director.general.dif@gmail.com>

महोदय,

कृपया उक्त विषयक संलग्नक ग्रहण करने का कष्ट करें।

भवदीय,

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (30प्र0)

**From:** Slbc Department , Up

**Sent:** Saturday, December 3, 2022 12:20 PM

**To:** Director General <directorgeneral.difup@gmail.com>; director.dif@gmail.com; 'SHIV SINGH' <director.general.dif@gmail.com>

**Subject:** FW: Draft minutes of the SLBC meeting held on 23.11.2022

महोदय,

कृपया उक्त विषयक संलग्नक ग्रहण करने का कष्ट करें।

भवदीय,



**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की सितम्बर 2022 तिमाही की दिनांक 23.11.2022 को  
सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त**

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की सितम्बर 2022 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 23.11.2022 को श्री दुर्गा शंकर मिश्रजी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में लोक भवन में सम्पन्न हुई। इस बैठक में डॉ० बालू केनचप्पा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ; श्री आलोक कुमार, आई.ए.एस. सचिव योजना विभाग, उ०प्र० शासन; श्री अनुराग यादव, आई.ए.एस. सचिव कृषि; श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, उ० प्र०; श्री संजय कुमार दोरा, मुख्य महाप्रबंधक, नाबाई, लखनऊ; सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी।

बैठक के प्रारम्भ में श्री ब्रजेश कुमार सिंह, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ०प्र० ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने प्रदेश में की जा रही बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों की अद्यतन प्रगति से सभा को अवगत कराया।

गत बैठक दिनांक 29.09.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि के उपरांत, उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण मानकों पर प्रदेश की स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्नवत प्रस्तुत किया:-

1. सितम्बर 2022 तिमाही के दौरान प्रदेश का कुल जमा रु 14 लाख 31 हजार करोड़ रहा है जो सितम्बर 2021 (रु 13 लाख 13 हजार करोड़) के तुलना में रु 1 लाख 18 हजार करोड़ बढ़ा है। साथ ही सितम्बर 2022 में कुल अग्रिम रु 7 लाख 51 हजार करोड़ रहा है जिसमें सितम्बर 2021 (रु 666897 करोड़) के स्तर से रु 84449 करोड़ वृद्धि दर्ज की गई है।
2. इस प्रकार प्रदेश कुल बैंकिंग व्यवसाय में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रु 62166 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए प्रदेश का कुल व्यवसाय रु 21 लाख 90 हजार करोड़ के स्तर पर पहुँच गया है।
3. प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्रदेश में अभी तक 8.42 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं जिसमें से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 49 लाख जन धन खाते खोले गये हैं।
4. सामाजिक सुरक्षा योजना यथा PMJJBY ( 131 लाख) और PMSBY ( 415 लाख) के तहत कुल 546 लाख नामांकन किए गए हैं। योजना के तहत लोगों को कवर करने के लिए अभी भी बड़ा स्कोप उपलब्ध



है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 11.53 लाख नामांकन करते हुए अभी तक कुल 71.65 लाख नामांकन किये जा चुके हैं।

5. सितम्बर 2022 को समाप्त तिमाही में प्रदेश का ऋण जमा अनुपात 53.07% रहा है जो मार्च 2022 के स्तर 52.38% से 0.69% की बढ़ोतरी दर्शाता है। अवगत करना है कि प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंको द्वारा ऋण जमा अनुपात बढ़ाये जाने हेतु समग्र रूप से कार्ययोजना बनाते हुए प्रयास किये जा रहे हैं।
6. विगत एस. एल. बी. सी. बैठक के दौरान राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत CDRatio (जो की क्रमशः 52.38% व 46.17% हैं) में भिन्नता पाए जाने पर विस्तृत चर्चा की गई थी। इस संबंध में, उन्होंने सभा को अवगत कराया कि RBI द्वारा प्रस्तुत BSR-7 रिपोर्ट में U.P. Cooperative Banks व UPSGV Bank का डाटा सम्मिलित नहीं किया जाता है जबकि एस. एल. बी. सी द्वारा प्रस्तुत CDRatio में इन दोनों बैंकों के Data को भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत जमा और ऋण धनराशि में U.P. Cooperative Banks, UPSGV Bank तथा उन सभी इकाइयों के ऋण को भी शामिल कर लिया जाये जिनका फाइनेंस प्रदेश से बहार स्थित बैंक शाखाओं/Cooperate office/Headoffice द्वारा किया गया है तब प्रदेश का CDRatio दोनों ही स्तर पर समान हो जाता है, जिसका विस्तृत विश्लेषण PPT के माध्यम से भी प्रस्तुत किया गया है।
7. RBI के निर्देशों के अनुसार, राज्य के सभी केंद्रों को 5 KM के दायरे में CBS- सक्षम बैंकिंग आउटलेट से संतुष्ट किया जा चुका है। प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं को विस्तार देने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा "ONE GP ONE BC" कार्यक्रम की प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत अब तक कुल 32,666 बी. सी. सखी को Onboard किया जा चुका है।
8. प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंकिंग आउटलेट में कुल 18,096 (10034 बैंक मित्र, 7664 बैंक सखी और 207 एटीएम) में बढ़ोतरी हुई है।
9. चालू वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक ऋण योजनांतर्गत आवंटित लक्ष्य रु 2,94,988 करोड़ के सापेक्ष सितम्बर 2022 को समाप्त तिमाही तक रु 1,42,537 करोड़ का ऋण वितरण करते हुए 48% की उपलब्धि हासिल की गयी है। हमारे प्रदेश में MSME Sector के अन्तर्गत कुल आवंटित लक्ष्य रु 78360 करोड़ के सापेक्ष रु 71409 करोड़ का ऋण वितरण करते हुए 91% की उपलब्धि हासिल की गयी है। साथ ही कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कुल रु 66786 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।
10. PMSVANidhi योजनांतर्गत हमारे प्रदेश में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों (10.33 लाख) के सापेक्ष 9.88 लाख आवेदन पत्र स्वीकृत एवं 9.56 लाख आवेदन पत्रों में वितरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।



11. सरकार प्रायोजित विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आदि में हमारे प्रदेश ने विगत वर्षों में लक्ष्यों के सापेक्ष शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है।
12. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनांतर्गत सितम्बर 2022 को समाप्त तिमाही तक प्रदेश में 29 लाखसे अधिक लाभार्थियों को ₹ 19245 करोड़ की धन राशी स्वीकृत कर वितरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की इस महत्वकांक्षीयोजना में गत 5 वर्षों से लगातार लक्ष्यों को पूर्णतयः प्राप्त किया जा रहा है।
13. हमें प्रदेश सरकार द्वारा RC Filed cases में Recovery हेतु निरंतर सहयोग प्राप्त होता रहता है। एक बार पुनः मैं प्रदेश सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरफेसी के अंतर्गत लम्बित मामलों में वसूली हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, 30 प्र० ने अपने संबोधन में सर्वप्रथम श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हुए प्रदेश में बैंकिंग विस्तार हेतु किये गए कार्य की सराहना की उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि सितम्बर 2022 तक प्रदेश में MSME के अन्तर्गत 90% लक्ष्य पूर्ण किये जा चुके हैं, तथा ACP के अंतर्गत 48% लक्ष्य हासिल किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि विगत एक वर्ष के दौरान प्रदेश के C:D ratio में 1.8% की वृद्धि हुए है | PMSVANIDHI के अन्तर्गत QR का वितरण भी किया जा रहा है। 100 विकास खण्ड में ट्रेनिंग का कार्य भी किया जा रहा है तथा जल्द ही यहाँ के LDMS को भी ट्रेनिंग देने का कार्य किया जायेगा |

सभा को अवगत करते हुए उन्होंने कहा की PM SVANidhi में अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि Border Area Development हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रदेश में 40% से कम ऋण जमानुपात वाले बैंकों की संख्या सितम्बर तिमाही में 02 हो गयी है जो कि जून तिमाही में 04 थी। उन्होंने अवगत कराया कि प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में कार्यरत बैंको द्वारा ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु किये जा रहे विभिन्न प्रयासों विशेषकर क्रेडिट आउटरीच कैम्पों के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु बैंकों की प्रशंसा की।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

डॉ० बालू केनचप्पा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने साथ ही प्रदेश शासन, समस्त बैंको व अन्य वित्त संस्थानों के अधिकारीगणों का अभिवादन करते हुए प्रदेश में बैंकिंग विस्तार हेतु किये गए कार्य की सराहना की।



प्रदेश के ऋण जमानुपात के विषय में सभा को अवगत कराते हुए डॉ०केनचप्पा ने कहा कि विगत 8 तिमाही में incremental ऋण जमानुपात में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है, अर्थात जमा राशि के सापेक्ष अग्रिम में वृद्धि दर अधिक दर्ज हुई है। उन्होंने जोर देते हुए प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि ऋण जमानुपात को और अधिक बेहतर करने हेतु प्रदेश में industrialization को गति देने कि आवश्यक है, जिससे बैंक को अधिक से अधिक अच्छे ऋण प्रस्ताव प्राप्त हो सकें।

श्री आलोक कुमार, आई.ए.एस., सचिव, आयोजना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने पी.पी.टी. के द्वारा प्रस्तुत अपने संबोधन में प्रदेश के C:D ratio, पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न प्रगति मापदंडों में चर्चा की। उन्होंने RBI website पर उपलब्ध दिसम्बर '21 के C:D ratio का संज्ञान लेते हुए कहा कि SLBC द्वारा प्रस्तुत आकड़ों तथा RBI website पर दिए गए C:D प्रतिशत में काफी अंतर है। इस सन्दर्भ में आप ने क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक से उपरोक्त विषय में विधिवत गवेषणा करने हेतु आग्रह किया।

श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश के विकास में बैंकों की महती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बैंकों द्वारा विभिन्न मापदंडों पर किये गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए सभा में उपस्थित प्रदेश सरकार एवं बैंकों के वरिष्ठ अधिकारीगण, को समीक्षा बैठक में निम्नवत सम्बोधित किया:

- मध्यांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में क्रेडिट-डिपॉजिट (सीडी) रेशियो 40% से कम है, इन क्षेत्रों के जनपदों में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रों एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण प्रवाह कम है। इन क्षेत्रों/जनपदों में ऋण प्रवाह बढ़ने हेतु सघन प्रयास किये जाये।
- ऋण जमानुपात में बैंकों के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है इसको वर्तमान में 53% से बढ़ाकर मार्च '23 तक 60% करने की नितान्त आवश्यकता है। उन्होंने जनपद मऊ में यथाशीघ्र 1000 करोड़ के ऋण मेले का आयोजन किये जाने हेतु निर्देशित किया। (कार्यवाही: यूनियन बैंक)
- Aspirational Blocks तथा Districts के विकास हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिये गये।
- सरकार जल्द ही Aspirational cities कि घोषणा करने जा रही है, भविष्य में इनके विकास हेतु भी विशेष कार्ययोजना बनाने कि आवश्यकता होगी।
- लोन मेला इत्यादि के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार कि साथ साथ insurance schemes से भी अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गये।
- सभी बैंकों सहित अन्य विभाग अपने CSR फण्ड का उपयोग Aspirational Blocks तथा Districts के विकास हेतु करने के निर्देश दिए गये।
- प्रदेश में लोकल इकॉनमी को बढ़ाये जाने हेतु विशेष व्यवसाय एवं ऋण प्रवाह किये जाने की कार्यवाही बैंकों द्वारा की जाये।



बैठक के दौरान ऋण जमानुपत पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रदेशके ऋण जमानुपत की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ०प्र० द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आकड़ों को आधार माना जायेगा। उन्होंने विगत 8 तिमाही में incremental ऋण जमानुपात में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर पर प्रसन्नता व्यक्त की।

अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने और प्रदेश के समग्र विकास के लिए हर एक सेक्टर के अल्पकालिक व दीर्घकालिक कार्ययोजना बनाई गई है और इसे सफल बनाने के लिए बैंक का रोल महत्वपूर्ण है। प्रदेश का विकास जितनी तेजी से होगा बड़ी इंडस्ट्री उतनी तेजी से यूपी की ओर आकर्षित होंगी और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अन्तर्राज्य परिषद के निर्देशों के अनुसार हमारे प्रदेश में 587 बैंकशाखा अथवा IPPB शाखा रहित केन्द्रों में से 344 केन्द्रों पर IPPB शाखा खोली जा चुकी है शेष बचे 243 केन्द्रों में सहकारी बैंकों की शाखा खोली जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही: प्रमुख सचिव सहकारिता एवं नाबाई)

कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रवाह बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा Agriculture Infrastructure Fund में भारत सरकार के द्वारा प्रदेश को दिए गए लक्ष्य ₹ 12,831/- करोड़ के सापेक्ष सम्बंधित विभाग को निर्देशित किया गया कि बैंको को लक्ष्य के सापेक्ष न्यूनतम 200% गुणवत्तायुक्त ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किये जाएं।

(कार्यवाही: कृषि विभाग)

मुख्य सचिव महोदय ने निर्देशित किया कि NABARD के RIDF फण्ड का प्रदेश के विकास हेतु सभी सम्बंधित विभागों के द्वारा उपयोग किया जाये।

(कार्यवाही: सभी सम्बंधित विभाग)

बैठक के अंत में श्री ब्रजेश कुमार सिंह, महाप्रबन्धक एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ०प्र० द्वारा बैठक में समय देने के लिए श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का विशेष आभार व्यक्त किया गया तथा उनके अमूल्य मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद दिया गया। उन्होंने प्रदेश शासन के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों तथा बैंको से पधारे स्टेट प्रमुख व अन्य समस्त सहभागियों का भी आभार व्यक्त किया जिनके सहयोग से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक संपन्न की जा सकी।

\*\*\*\*\*